जंग जंगों के फलस्वरूप के खिलाफ़: 45वाँ न्यूज़लेटर (2020)

क्योंकि सवदान (जापान), अमेरिकी बमबारी से बचने के लिए वियतनाम में एक माँ और उसके बच्चे एक नदी में उतर गए, 1965।

प्यारे दोस्तों,

ट्राइंटीकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान की ओर से अभिवादन।

अक्टूबर के मध्य में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने चकित कर देने वाले ऑक्सिड के साथ अपनी वल्लई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। आईएमएफ़ का मानना है कि साल 2020 के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.4% की गिरावट आएगी, जबकि 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% की वृद्धि देखी जा सकेगी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ-साथ ब्राजील और भारत जैसे बड़े देशों की आर्थिक गतिविधियों में ढहराव और गिरावट बनी रहेगी। लेकिन यूरोप में कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो जाने के बाद और ब्राजील,
भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका में संक्रमण की अनियंत्रित पहली लहर के देखते हुए लगता है कि आईएमएफ़ के अनुमान अभी और नीचे जा सकते हैं।

वहीं, चीन के ऑक्डो काफ़ी हैरान हुए। अकेला चीन पूरे विश्व विकास में 51% का योगदान करेगा। आईएमएफ़ के ऑक्डों के अनुसार, चीन के अलावा विश्व आर्थिक विकास में वे एशियाई अर्थव्यवस्थाएं मुख्य योगदान देंगी, जिनके चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। ये देश हैं, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया। चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने लॉकडाउन के चलते साल 2020 के लिए कोई भी विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। लेकिन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में, एनडीआरसी के प्रमुख निगम जिख्शे ने कहा कि साल 2021 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, हालांकि उन्होंने दोहराया कि केवल जीडीपी का विकास करना ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में लगातार सुधार के द्वारा गरीबी क्षत्र करना विकास का लक्ष्य होगा। इस बैठक के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उप प्रमुख, यू जुगुन ने बताया कि कोरोनावायरस से पैदा हुए व्यवधानों के कारण गरीब हो गए एक करोड़ परिवारों को अब गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है।
ज़रीना हाशमी (भारत), तबाह कर दिए गए शहरों में से एक सरेबेकिता, 2003।

कोरोनावायरस के कारण जारी अवरोधों और वैक्सीन के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए, दुनिया के देशों के लिए तनाव
कम कर आपसी सहयोग बढाना ही उपयुक्त होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित, संक्रमण चक तोड़ने के लिए सुचना और कमियों के आदान-प्रदान की पहल जज्रे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राणियों को पुन: अभ्यस्त करने की दिशा में काम कर सकता है। लेकिन कोरोनावायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका-इसमें इनकार करते हैं (जबकि दूसरी ओर चीन और जपान जैसे समाजवादी देश इस आदान-प्रदान को बढ़ावा दे रहे हैं)।

परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका 'वैक्सीन राष्ट्रीय' का एंजैंडा चला रहा है और वाकी दुनिया के नौरू की छिंद़ छोड़ दो हर संभव उपाय कर केवल अमेरिकी के लिए वैक्सीन सुरक्षित कर लेना चाहता है। लेकिन वायरस सीमात में नहीं देखता। यही कारण है कि चीन और जपान ने 'जनता के लिए वैक्सीन' का आहवान किया है। चीन अब औपचारिक रूप से COVAX सहयोग में शामिल हो गया है; ये मंच नए अन्य संस्थानों के द्वारा ‘COVID-19 के विस्तृत वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुमंडल, विकास और वितरण करने वालों की मदद करने’ के लिए बनाया गया है। इस मंच में 184 देश शामिल हैं, हालांकि प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों इसमें शामिल नहीं हैं। एक प्रेस बूथ में जायंट फॉर फंडिंग के नए अध्यक्ष ने कहा, ‘चार संभावना वैक्सीन के स्वेच्छालिन करने के रूप में अधिक संभव देशों को ‘COVAX’ में शामिल होने और समझौते करने के लिए प्रेरित करना।'

एक और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहल की जा रही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल होने के बजाय पूरी उत्तराधिकारी की भूमिका को कम करने में जुटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में, 'रोब्वींच अमेरिका’ के नाम से एक परियोजना शुरू की है; जिसका उद्देश्य चीन द्वारा किए गए सार्वजनिक निवेशों को बाहर करने के लिए अमेरिकी निजी क्षेत्र के फंड को आकर्षण करना है। चीन के बेडर एंडर रोड परियोजना की चुनौती देने के लिए अमेरिका ने अधिक और एशिया में मामूली फंड बोर्ड के नाम पर फंडिंग पेशेवर कोरोना बनाया है। इन निवेश उपायों के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ चर्चाएं जारी रखीं। जब अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री (पम्पियो) और रक्षा मंत्री (एस्पर) भारत और एशिया तक, एक बैनल एक्सवेज़ एंड कोऑपरेटन एमीयन्ट (BECRA) पर हस्ताक्षर किए गए तब, इस महत्वपूर्ण समझौते के निम्नलिखित बहुमत बनाने के लिए ट्राइडिस्टेंटितल: सामाजिक जोड़ संस्थान ने भारत का कम्युनिस्ट पार्टी (माक्संबादी) के पार्टी प्रमुख ब्रॉनस्टो और सराइनरिटी एस्टाइल के द्वारा नेपाल और इंडिया-यूएस एस्ट्रेंडिक रिलेशन्स (लेफटवर्ड, 2007) के लेखक प्रकाश करते से बात की।
ट्राइकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोभ संस्थान: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर का कहना है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की ‘गठबंधन प्रणाली’ का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीईसीए के हस्ताक्षर के साथ ऐसा लगता है कि अब वे हिचकिचाहट दूर हो गई है। क्या भारत अब पूरी तरह से चीन के बिनाफ अमेरिका के साथ गठबंधन में है?

प्रकाश करात: अमेरिका और भारत के बीच सैन्य गठबंधन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अब हम जो देख रहे हैं वह वो रक्षा संरचना समझौता है जिसपर 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने हस्ताक्षर किया था। दस साल बाद, 2015 में मोदी सरकार ने इस संरचना का नवीनीकरण किया। उस संरचना के विभिन्न पहलुओं को संस्थागत करने का काम अब
बीईसीए पर हस्ताक्षर के साथ पूरा हो गया है। मोदी सरकार के साथ आने के बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई थी। 2016 में सस्ता आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तब पहली बार, भारत ने अपने बंदरगाहों और हवाई-अड्डों पर किसी विदेशी देश के सशस्त्र बलों को सैन्य, सम्पत्ति या रक्षा के लिए रखने पर सहमति व्यक्त की थी। यह एक नई संधी क्राउट बैंसिंग समझौतों की तरह है, जो अमेरिका के अपने नाटो सहयोगियों के साथ है। इसके बाद मार्च में आपूर्ति किए गए अमेरिकी संचार उपकरणों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए COMCASA [कम्प्यूटरजन्मन कमेंटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्लानपेट] समझौता किया गया और भू-मानसिक सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इन सभी तरीके सूचीबद्ध समझौते के साथ, भारतीय सशस्त्र बलों को अमेरिकी सेना के साथ जोड़ दिया है। सन्तुष्टा समझौते में तीसरे देशों में संयुक्त कारवाई का भी प्रावधान है।

यदि यह संरचना पुनः गठबंधन नहीं है, तो यह क्या है? विदेश मंत्री इस बुद्धि को बनाए रखने के लिए कारोबार कर रहे हैं कि भारत किसी भी गठबंधन प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

ट्राइकोनिटेंटल: सामाजिक शोध संस्थान: युद्ध की जो योजना बनाई जा रही है, उसमें सभी क्वाड सदस्यों को शामिल किया गया है। क्या यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?

प्रकाश कार्तिक: बुधवारी नागरिक न चाहिए 2007 में की गई थी, जिसमें जापान, ओस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल थे। लेकिन तब इस विषय में समझौते का होना नहीं किया गया। चीन ने इस चीन-विरोधी मंच पर आपूर्ति जताया था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के आदेश से, इस मंच को स्थगित किया जा रहा है। चीन ने इस मंच के लिए अपना समर्थन लेने लगा था। लेकिन इसे बाद में, चीन ने इस मंच के लिए अपना समर्थन नहीं दिया।

2017 में, ट्रप्प प्रशासन की इंडो-पैसिफिक रणनीति के हिस्से के रूप में विदेश मंत्री रूप में क्राउट को पुनः स्थापित किया गया। अभियान के समय में, इसे सीसीएफका रणनीति कहा जाता था। अमेरिका द्वारा, चीन के प्रति जाति और आक्रमणों के बढ़ते समय, विदेश रूप में बदल हो गया है। मालाबार अभाव, अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच पिछले दशकों से चल रहे वाणिज्यिक संयुक्त रूप से अभाव योजना अभाव था। वाणिज्यिक बल नौसेना अभाव था। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आदेश के पारंपरिक सहयोग की तलाश नहीं करने के बजाय, चीन को इस रूप में मिलने लगा।

क्या वाद का महत्व यही है कि इसमें साफ हो जाता है कि भारत अमेरिका का एक पारंपरिक सहयोगी बन गया है, अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों जापान और ओस्ट्रेलिया की तरह। इसिया में चीन को रोकने के लिए भारत ने एक रणनीति की शुरुआत की।

ट्राइकोनिटेंटल: सामाजिक शोध संस्थान: क्या भारत के लिए महत्वपूर्ण भारत की विशेष रूप से भारत अभाव के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?

प्रकाश कार्तिक: महामारी के बाद, भारत को अपनी स्थिति सुधारने और विकास की जाति के लिए चाहिए विदेशी सहयोगी बनाने के लिए भारत के साथ अपने आधिकारिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। इस तय से देखते हुए कि चीन की अर्थव्यवस्था वित्तीय आधिकारिक सहयोग में महत्वपूर्ण समय लगने चाहिए। चीन के साथ विवाद और व्यापार प्रतिबंधित करने के बाद में संबंध अदुरदिश्न्त है। कृत्रिम प्रतिवेदन तो लगाए गए थे, जो चीन को भारत अभाव के लिए भारतीय विवाद में अनुसरण करने पर बढ़ावा दें।

भारत-चीन सीमा मुट्ठी को उच्च-स्तरीय वातांकों के माध्यम से हल करना और इसके बाद के अन्य क्षेत्रों के संबंधों को प्रभावित नहीं होने देना भारत के हित में होगा। लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी [सत्साहू दूता] का इस पर ध्यान नहीं देता है।
के. जी. सुब्रह्मण्यन (भारत), शहर जलाने के लिए नहीं है, 1993।

1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ, तब अपनी पीढ़ी के महान उद्देश्यों में से एक साहित्य लुकियानी ने ऐशरीफ़ इंसानों कविता लिखी। कविता युद्ध के अत्याचारों से शुरू होती है, और बताती है कि युद्ध आग
और खुनख़राबा, भुखमरी लेकर आता है। साहिर जनता का खुन बहाने वाली जंग के बजाए पूँजीवाद के खिलाफ जंग छुड़ने का सुझाव देता है।

ये हमारे समय के लिए जरूरी शब्द हैं।

स्नेह सहित,
विजय।

I am Tricontinental:
Nitheesh Narayanan. Researcher, Interregional office.
I am working on documenting AK Gopalan, the leader of communist wing in Indian parliament for 25 years (1952-77), as a parliamentarian. I am in search of the original texts of the speeches he delivered inside the parliament on various issues and also his role as a communist parliamentarian. This will be published as a book. I'm also writing a short bio of KS Ammukkutty, a veteran dalit-women-agricultural labourer-communist leader for northern Kerala. I am working with the Boficha Appeal for peace and also assisting the construction of the International Union of Left Publishers.
रहा हूँ। इस किताब का मक़सद है, एक कम्युनिस्ट होने के नेता उनकी संसद के सदस्य होने की भूमिका पर प्रकाश डालना।
इसलिए, मैं उनके द्वारा संसद के अंदर विभिन्न मुद्दों पर दिए गए भाषणों के मूल लेखों की तलाश कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं उत्तरी केरल की एक अनुभवी दलित-महिला-कृषि मंज़िल-कम्युनिस्ट नेता, के एस अम्बुकटी की संक्षिप्त जीवनी भी लिख रहा हूँ। मैं बोफ़चा अपील फोर पीस के साथ काम कर रहा हूँ और अंतरराष्ट्रीय यूनियन ऑफ़ लेफ्ट पब्लिशर्स के निर्माण में भी सहायता कर रहा हूँ।